संरक्षणवाद की दीवार खड़ी कर रहे हैं विकसित देश : निर्मला

नई दिल्ली, 20 अप्रैल(भाषा)।

भारत ने गुरुवार को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देशों द्वारा अपनी वीजा व्यवस्था को सख्त करने पर चिंता जताई। इसके साथ ही भारत ने सेवाओं के व्यापार को लागू करने को विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) समर्थित वैश्विक ढांचे पर जोर दिया है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को यहां कहा कि भारत ने डब्लूटीओ को एक प्रस्ताव देकर सेवाओं में व्यापार सुविधा पर करार की मांग की है।

उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों का उदाहरण दिया जो कुशल पेशेवरों की आवाजाही के लिए अपनी वीजा व्यवस्था को कड़ा कर रहे हैं। सीतारमण ने कहा- अब विभिन्न देश सेवाओं के व्यापार के मामले में स्पष्ट तौर पर संरक्षणवाद की दीवार खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह समय है जबकि सेवाओं के व्यापार के लिए हमारे पास वैश्विक ढांचा होना चाहिए। हम सक्रिय तौर पर अपनास प्रस्ताव डब्लूटीओ में आगे बढ़ाएंगे।

सेवाओं में व्यापार सुगमता करार का मकसद पेशेवरों की आवाजाही के नियमों में ढील और लेनदेन की लागत को कम करने के लिए अन्य कदम उठाने से है। भारत डब्लूटीओ में इस करार को लेकर दबाव बना रहा है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 60 फीसद है। यह क्षेत्र कुल रोजगार का 28 फीसद प्रदान करता है।

सीतारमण ने कहा कि भारत चाहता है कि सभी सदस्य देश दिसंबर में अर्जेंटीना में डब्लूटीओ की मंत्री स्तरीय बैठक से पहले इस प्रस्ताव का अध्ययन करें। एच-1 बी वीजा पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दस्तखत किए जाने के बारे में सीतारमण ने कहा कि अमेरिका ने इसमें से कुछ निश्चित संख्या में वीजा भारत को देने की प्रतिबद्धता जताई है। हम निश्चित तौर पर चाहेंगे कि अमेरिका अपनी इस प्रतिबद्धता को पूरा करे।